जनसत्ता

7 अक्तूबर, 2019

संबंधों का विस्तार

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। शनिवार को उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान कई मसलों पर समझौते भी हुए, जिनमें शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। शेख हसीना की यह भारत यात्रा कई मामलों में महत्त्वपूर्ण है। एक ऐसे समय में जब भारत सरकार राष्ट्रीय नागरिक पंजी तैयार कर रही है और उसमें यहां रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के सबसे अधिक प्रभावित होने की चर्चा है, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री का यहां आना और दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में उस मसले पर बातचीत करना उल्लेखनीय बात है। शेख हसीना ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी पर अपनी चिंता जाहिर की, पर भारत ने उन्हें संतुष्ट किया कि सारी प्रक्रिया अदालत की निगरानी में पूरी हो रही है, इसलिए इसे लेकर ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा दोनों नेताओं की बातचीत में रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा भी उठा और दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि म्यांमा के रखाइन क्षेत्र में उनकी सुरक्षित वापसी होनी चाहिए।

बांग्लादेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई से पार पाना कठिन बना हुआ है। ऐसे में भारत से उसके व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, वहां बेहतरी के कुछ रास्ते खुलेंगे। शेख हसीना की इस यात्रा में पहले से चले आ रहे व्यापारिक समझौतों को बरकरार रखते हुए चटगांव और मंगला बंदरगाहों को भारतीय पोतों को माल ढुलाई के लिए खोलने पर सहमति बनी। पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं, इस यात्रा से उन्हें और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा तीस्ता नदी के जल बंटवारे से संबंधित विवाद को जल्दी ही सुलझा लेने का संकल्प दोहराया गया और बांग्लादेश की फेनी नदी का पानी त्रिपुरा के सबरूम में पेयजल के लिए उपलब्ध कराने पर रजामंदी हुई। दोनों नेताओं ने पूर्वोत्तर भारत में रसोई गैस आपूर्ति संबंधी परियोजना का उद्घाटन किया। शेख हसीना की इस यात्रा में उल्लेखनीय समझौता दोनों देशों के बीच सीमाओं को सुरक्षित बनाने को लेकर है। दोनों नेताओं ने अपने सीमा प्रहरियों को सीमा पर बाड़ लगाने की प्रक्रिया के शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया। इस तरह शेख हसीना के भारत आने से उन तमाम आशंकाओं पर विराम लगा है, जो राष्ट्रीय नागरिक पंजी को लेकर जताई जा रही थीं।

भारत इन दिनों आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगाने के तमाम पक्षों पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी इस जरूरत को रेखांकित किया कि जब तक दुनिया के देश इस मुद्दे पर बंटे रहेंगे, तब तक इस पर काबू पाना कठिन बना रहेगा। छिपी बात नहीं है कि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सबसे अधिक बढ़ावा पाकिस्तान से मिल रहा है। उस पर नकेल कसने के लिए जरूरी है कि पड़ोसी देशों को भी चाकचौबंद बनाया जाए। इस लिहाज से बांग्लादेश के साथ आतंकवाद पर काबू पाने के लिए हुए समझौते महत्त्वपूर्ण हैं। तटीय निगरानी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश से जुड़ी समुद्री सीमा में भारत करीब दो दर्जन राडार प्रणाली लगाएगा। छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकी संगठन बांग्लादेश की सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते रहे हैं। इस तरह वहां की समुद्री सीमा पर निगरानी चौकस रखने की जरूरत है। नए समझौते से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

घटना और सबक

इस साल बालाकोट में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले के अगले दिन यानी सत्ताईस फरवरी को भारतीय वायुसेना ने अपनी ही मिसाइल से अपना एमआइ-17 हेलिकॉप्टर मार गिराया था। यह घटना गफलत का परिणाम थी। हालांकि तब पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत का एक हेलिकॉप्टर मार गिराया है, लेकिन बाद में वह झूठा साबित हुआ। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने इस घटना को बड़ी चूक मानते हुए स्वीकार किया है कि हमने अपना ही हेलिकॉप्टर मार गिराया था। हालांकि शुरुआती जांच में यह साफ हो गया था कि वायुसेना का हेलिकॉप्टर अपने ही सैनिकों ने भूलवश मार गिराया था, लेकिन अब विस्तृत जांच के बाद आधिकारिक रूप से वायुसेना प्रमुख ने इसे माना है। इस हादसे में एक पायलट सहित वायुसेना के छह जवान शहीद हो गए थे। घटना की जांच में जो चीजें निकल कर आई हैं, वे गंभीर और चौंकाने वाली हैं और सीधे-सीधे सैन्य अभियानों की तैयारियों से जुड़ी बड़ी खामियों की ओर इशारा करती हैं। हालांकि सेना की तैयारियों और उसकी गंभीरता को लेकर कोई संदेह नहीं, पर इनमें जो त्रुटियां रह जाती हैं, वे भारी पड़ती हैं। इसलिए आम आदमी के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हमारी वायुसेना इतनी अत्याधुनिक है तो फिर कैसे ऐसी बड़ी चूक हो सकती है कि हम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपना ही नुकसान कर बैठें।

आखिर गलती कहां हुई, यह बड़ा प्रश्न है। अपने ही हेलिकॉप्टर के बारे में क्यों नहीं पता चल पाया? सवाल ज्यादा गंभीर इसलिए भी है कि मामला युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हेलिकॉप्टर और विमानों से जुड़ा है और इसमें जोखिम के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। वायुसेना प्रमुख ने बताया है कि एमआइ-17 हेलिकॉप्टर की संचार प्रणाली दुरुस्त नहीं थी। ऐसे युद्धक हेलिकॉप्टरों में एक संचार तंत्र काम करता है जिससे यह पता चल सकता है कि हेलिकॉप्टर दुश्मन देश का है या अपना, लेकिन इस हेलिकॉप्टर में यह प्रणाली काम नहीं कर रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जमीन पर नियंत्रण कक्ष को संकेत ही नहीं मिल पाए कि यह हेलिकॉप्टर अपना है। इसी भ्रम में इसे दुश्मन देश का समझ कर उस पर मिसाइल दाग दी गई। यह घटना सैन्य कार्यों में लगे सैनिकों और तकनीकी कर्मचारियों के बीच तालमेल की भारी कमी को भी उजागर करती है। सवाल है कि आखिर उस हेलिकॉप्टर का संचार तंत्र पूरी तरह से काम क्यों नहीं कर रहा था। क्या अभियान पर भेजे जाने से पहले इस तरह की कोई पुख्ता जांच नहीं होती और चीजों को सामान्य मान कर चलने दिया जाता है? अगर ऐसा है तो यह बड़ी लापरवाही है जिसकी कीमत छह सैनिकों की शहादत के रूप में चुकानी पड़ी है। यह तो साफ है कि वायुसेना आधुनिक होने के भले कितने ही दावे करे, लेकिन तकनीकी खामियां दूर करने में संबंधित विभाग ने लापरवाही बरती है। युद्ध क्षेत्र में भेजे जाने वाले विमानों, हेलिकॉप्टरों को तो हमेशा पूरी तरह दुरुस्त रखा जाना चाहिए। एक भी छोटी-सी भूल जानलेवा बन सकती है। भारतीय वायुसेना को ऐसी घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। सवाल एक विमान या हेलिकॉप्टर की कीमत से कहीं ज्यादा बड़ा जाबांज सैनिकों की जिंदगी से जुड़ा होता है। अगर छोटी-छोटी लापरवाही, चूक ऐसे हादसों को जन्म देती रहेंगी तो कैसे हम दुश्मन के सामने टिक पाएंगे?

कल्पमेधा

जिन विषयों के लिए प्रमाण नहीं होते, वे बातें विशेष उन्माद के साथ मानी जाती हैं।

-बर्ट्रेंड रसेल

खतरे में हांगकांग की संप्रभुता

ब्रह्मदीप अलूने

पिछले साल शी जिनपिंग ने चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद का दृष्टिकोण रखते हुए कहा था कि खुलेपन से तरक्की का रास्ता खुलता है और चीन पहले से अधिक खुलापन लाएगा। हांगकांग में एकाधिकार कायम करने की चीनी जल्दबाजी से साफ है कि चीन ताकत के सहारे सब कुछ हासिल करने पर भरोसा करता है। चीन संपन्नता से एकाधिकार करना चाहता है, जबकि आर्थिक संपन्नता के साथ ही सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र से ही विकास का मार्ग सुनिश्चित हो सकता है।

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल में एक भाषण में चीनी शब्द 'डूजेंग' का इस्तेमाल कई बार किया। इस शब्द का मतलब होता है- संघर्ष करना। जिनपिंग ने संघर्ष को चीन की नियति बताते हुए उग्र राष्ट्रवाद को हवा देने की कोशिश की और इसके जरिए उन्होंने अपनी उन नाकामियों पर परदा भी डाला जिनसे उनका देश इस समय जूझ रहा है। माओ की आक्रामक नीतियों के विरोधाभास के बीच सत्तर सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन कर उभरने वाले चीन के राष्ट्रपति इस समय बैचेन हैं। चीन इस समय अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में बुरी तरह उलझा हुआ है और उसकी विकास दर भी लगातार गिर रही है। वीगर मुसलमानों पर अत्याचार की गूंज पूरे विश्व में है। इन सबके बीच चीनी अर्थव्यवस्था के केंद्र बन चुके हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं और चीनी आधिपत्य को खुली चुनौती दे रहे हैं।

इस महीने की शुरुआत में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के सत्तर साल पूरे होने के अवसर पर चीन की खुशियां हांगकांग में चीन विरोधी काले दिवस और हिंसक प्रदर्शन के आगे फीकी पड़ गईं। पिछले कुछ सालों से हांगकांग का समाज इस बात से आशंकित है कि चीन उनके यहां लोकतंत्र को खत्म कर देगा और इसी आशंका ने चीन विरोधी भावनाओं को भड़का दिया है। अब यहां के लाखों नागरिक पिछले कई महीनों से सरकारी दफ्तरों, चीन की सेना के स्थानीय मुख्यालय और शहर की संसद के बाहर जमा होकर चीनी नीतियों के विरोध में व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार अति-आधुनिक हांगकांग हिंसा के दलदल में फंसता जा रहा है।

उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जीने के आदि हो चुके हांगकांग को चीनी पहचान स्वीकार नहीं है। हांगकांग में सिविल ह्यूमन राइट्स फ्रंट वह अगुआ संगठन है जो चीनी सरकार की नीतियों के विरोध में लोगों को लामबंद किए हुए है। इस संगठन के नेताओं का कहना है कि लोगों का पुलिस पर भरोसा नहीं है और पुलिस भी लोगों पर भरोसा नहीं कर रही है। चीनी सेना शांतिप्रिय हांगकांग को घेर रही है और यह दबाव अंततः हांगकांग को गंभीर संकट की ओर धकेल रहा है। जनवादी चीन के आधिपत्य में 1997 में आए हांगकांग को विकसित दुनिया का मुकुट कहा जाता है, लेकिन इस समय यह क्षेत्र गहरे प्रशासनिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है। ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त होकर चीन के आधिपत्य में आई हांगकांग की युवा पीढ़ी को चीन पर भरोसा ही नहीं है। हांगकांग की संसद में घुस कर प्रदर्शनकारी नौजवान ब्रिटिश कालीन झंडा फहरा कर अपना गुस्सा जता चुके हैं। चीन के राष्ट्रीय गान के प्रति कई मौकों पर असम्मान दिखता है। इस साल जून में हांगकांग की सड़कों पर हिंसा का खौफनाक मंजर सामने आया था। इसके बाद से ही हांगकांग सुलगा हुआ है। इसका असर चीन की शक्तिशाली सत्ता पर भी पड़ा है।

हांगकांग 1841 से 1997 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन ने उसे 'वन कंट्री टू सिस्टम' (एक देश और दो प्रणाली) समझौते के तहत चीन को सुपुर्द किया था। यह समझौता हांगकांग को ऐसे आजादी और लोकतांत्रिक अधिकार देता है, जो चीन के लोगों को हासिल नहीं हैं। हांगकांग चीन का हिस्सा है, लेकिन उसे 'विशेष स्वायत्तता' मिली हुई है। ये स्वायत्तता 2047 में खत्म हो जाएगी और हांगकांग में रहने वाले कई लोग नहीं चाहते कि हांगकांग का वही हाल हो जो साम्यवाद की जकड़न में किसी क्षेत्र का होता है। इस बीच चीन तेजी से हांगकांग की सत्ता हथियाने को तत्पर नजर आ रहा है और इसी से हांगकांग की नौजवान पीढ़ी परेशान है।

वास्तव में चीन और ब्रिटेन के बीच समझौते के अनुसार हांगकांग को एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत पर काम करना था। वर्ष 2047 तक उसे विदेश और रक्षा मामलों को छोड़ कर राजनीतिक और आर्थिक आजादी हासिल है। इस समझौते के बाद हांगकांग विशेष प्रसासनिक क्षेत्र बन गया। इसके पास अपनी कानूनी व्यवस्था, बहु-राजनीतिक पार्टी व्यवस्था और अभिव्यक्ति और इकट्ठा होने की आजादी थी। इन विशेष अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र के पास अपना छोटा संविधान है। इसे 'बेसिक लॉ' कहा जाता है, जो घोषित करता

है कि इसका मूल उद्देश्य 'सार्वभौमिक मताधिकार' और 'लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं' के माध्यम से इस इलाके का नेता यानी मुख्य कार्यकारी चुनना है।

साल 2014 में बेजिंग ने कहा था कि वह मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के सीधे चुनाव की इजाजत देगा, लेकिन केवल पहले से अधिकृत उम्मीदवारों की सूची से ही इनका चुनाव होगा। 2014 में ज्यादा लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के साथ 'ऑक्यूपाई सेंट्रल प्रोटेस्ट' हुआ था, जहां आंदोलनकारियों ने पुलिस के आंसू गैस हमले से बचने के लिए छाते थामे और इसे अंब्रेला मूवमेंट कहा गया। इस घटना से चीन की वैश्विक छवि पर विपरीत असर पड़ा। हालांकि उनयासी दिन के आंदोलन के बाद भी चीन ने अपनी योजना को खारिज नहीं किया।

लेकिन कुछ महीने पहले आए प्रत्यर्पण कानून का हांगकांग में व्यापक विरोध हुआ और चीन को अंततः इसके आगे झुकना पड़ा। प्रत्यर्पण कानून के व्यापक विरोध के बाद चीन और हांगकांग की सरकार को कदम पीछे खींचना पड़े। हांगकांग की सीईओ कैरी लैम ने हिंसा रोकने के लिए एलान किया कि सरकार ने प्रत्यर्पण कानून को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। चीन ने भी उनके इस एलान का समर्थन किया, लेकिन हांगकांग की जनता को न तो अपनी सरकार पर भरोसा है और न ही चीन पर। इस कानून के मुताबिक हांगकांग के लोगों को मुकदमे के लिए चीन भेजा जा सकता था। हांगकांग वासियों को डर था कि इससे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा सकता है। साथ ही ये हांगकांग को मिली स्वायत्तता का भी हनन है।

चीन ने अपने फैसले पर अस्थायी रोक लगा कर हांगकांग के लिए एक फौरी राहत तो दे दी, लेकिन इससे लोगों में आशंका बढ़ गई। चीन ने लगातार हांगकांग के लोगों के अधिकारों में कटौती की है। जहां तक स्वायत्तता की बात है, इस शहर को स्वायत्तता तो दी गई है और चुनाव भी कराने का अधिकार है, लेकिन पूर्ण लोकतंत्र यहां लोगों को नसीब नहीं है। हांगकांग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि चीन हांगकांग की राजनीति में कई तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है और यहां की उदार राजनीतिक परंपरपराओं को नजरअंदाज कर रहा है।

हांगकांग के आंदोलनकारियों में अधिकांश युवा हैं। वहीं, चीन के समर्थन में भी एक समूह है जो लोकतंत्र के पक्ष में खड़े नेताओं को निशाना बना रहा है। जाहिर है, चीन की जल्दबाजी के चलते एक विकसित और अत्याधुनिक क्षेत्र गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल शी जिनपिंग ने चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद का दृष्टिकोण रखते हुए कहा था कि खुलेपन से तरक्की का रास्ता खुलता है और चीन पहले से अधिक खुलापन लाएगा। हांगकांग में एकाधिकार कायम करने की चीनी जल्दबाजी से साफ है कि चीन ताकत के सहारे सब कुछ हासिल करने पर भरोसा करता है। चीन संपन्नता से एकाधिकार करना चाहता है, जबकि आर्थिक संपन्नता के साथ ही सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र से ही विकास का मार्ग सुनिश्चित हो सकता है। हांगकांग के युवा कहते हैं कि अपनी ताकत के बल पर चीन लोकतंत्र को नहीं दबा सकता।

हरी घास पर कुछ देर

प्रयाग शुक्ल

दुनिया मेरे आगे

जब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' का कविता संग्रह 'हरी घास पर क्षण भर' आया तो हिंदी कविता के बहुतेरे नए-पुराने पाठकों ने कुछ चौंक कर यह पहचाना था कि आज की शहरी 'हरी घास' भी कविता की एक विषय वस्तु हो सकती है। वह हरी घास, जो वेनु बजाने और धेनु चराने वाले कृष्ण के समय की हरीतिमा से अलग प्रकार की घास है। हां, अज्ञेय की कविता के शीर्षक से ही जो छवि उभरी, वह किसी पार्क की हरी घास की ही छवि हो सकती थी। थी भी वही। और यह जो बागों-उद्यानों, पार्कों और रिहायशी इमारतों के परिसरों या बंगलों के लॉन की हरी घास है, वह आज के शहरातियों के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। उस पर या उसके बीच बैठ कर प्रकृति के साथ होने का कुछ तो एहसास होता ही है। आमतौर पर उसके आकर्षण में खिंची आकर गिलहरियां भी कुछ उछल-कूद करती हैं। कुछ चिड़ियां अपने पांवों उस पर चलती हैं। सुबह की सैर करने वाले कुछ नागरिक भी अपने जूते या चप्पल उतार कर उस पर कुछ देर चलना पसंद करते हैं। प्रेमी जोड़े उस पर बैठ कर बतियाते हैं। अपना सुख-दुख, प्रेम साझा करते हैं। बच्चे उस पर उछलते-कूदते हैं, खेलते हैं। उनकी मां और उनकी आया भी हरी घास के बीच होने का आनंद उठाती हैं। अच्छी हवा चल रही हो तो यह भी मनाती हैं कि सूरज का प्रकाश उसके डूबने से पहले कुछ देर और थमा रहे, तो कितना अच्छा हो। मन में ही यह कामना भी करती हैं कि प्रकाश थमे, पर हवा न थमे! हरी घास के बीच वाले झूले भी भला किसे अच्छे नहीं लगते! तो हरी घास की यह कामना उस पर 'क्षण भर' बैठने की इच्छा, भला किसके भीतर नहीं होती!

यह लिखते हुए मैं अपने रिहायशी परिसर के एक लघु-उद्यानी एरिया में एक बेंच पर बैठा था पेड़ की छाया के नीचे। चंपा के पेड़ों के कुछ सफेद फूल झर कर घास के कुल 'फ्रेम' की किनारी पर पड़े हुए थे। सूखे-झरे पत्तों के साथ। एक गिलहरी आ गई और दो पीली तितलियां भी हवा पर सवार एक ओर को चली गईं। कुछ बादल के साथ इस मौसम में यह दृश्य कुछ और मनोरम हो उठा। हां, एक चींटी ने घुटने के पास तक चढ़ कर और च्यूंटी काट कर यह भी बता दिया कि घास पर या उसके पास किसी कुर्सी या बेंच पर बैठने का सुख उठाना चाहोगे तो मेरी च्यूंटी भी सहनी ही पड़ेगी, कभी न कभी, क्योंकि तुम्हारी तरह उसे भी बहुत पसंद है हरी घास। वह चींटी तो यहीं घर बना कर रहने भी लगती है।

मैंने सोचा कि नवंबर-दिसंबर में जब दिल्ली एनसीआर में, यानी दिल्ली-नोएडा-गुड़गांव में ठंड पड़ रही होगी तो मैं हरी घास के बीच हर साल की तरह फिर कुर्सी डाल कर या किसी बेंच पर ही बैठ कर लिखा-पढ़ा करूंगा। जब लिखते-पढ़ते-सोचते कुछ देर विराम लूंगा, इधर-उधर देखूंगा और हरी घास के साथ फूलों-तितलियों और धूप के टुकड़ों के साथ भी हो लूंगा। हां, गिलहरियां भी आएंगी ही! पिछले साल तो एक तितली काफी देर तक घास पर जमी रही थी और मैं मोबाइल से उसकी एक तस्वीर खींच कर मित्रों को भेजा भी था।

महानगर में रहने वालों को यह हरी घास न मिले तो जरा सोचिए उनका क्या हाल होगा! हरी घास का एक टुकड़ा ही सही, बहुमंजिली सीमेंटी कंक्रीटी इमारतों के बीच आंखों और मन को कुछ सुख तो पहुंचाता ही है। सो, अचरज नहीं कि जो 'टेरेस गार्डेन' में आठवीं-दसवीं मंजिल की छत पर घास उगा लेने का साधन रखते हैं, वे वहां हरी घास उगा लेते हैं। फिर वह नकली हरी घास भी तो है ही, जो घास का भ्रम देने के लिए उगा ली जाती है कि आंखें को कुछ राहत मिले।

हरी घास को ठीक ही 'हरे गलीचे' की भी संज्ञा दी जाती है। पर एक दिन यह देख कर अचरज भी कम नहीं हुआ कि हमारी सोसायटी के पास की एक और सोसायटी की हरी घास को हटा कर वहां सीमेंटी फर्श बिछाया जा रहा है, क्योंकि हरी घास वाला मिट्टी का इलाका बारिश में कीचड़ पैदा करता है।

कितनी विडंबनाएं है शहरी जीवन की। कुछ हमने खुद रच डाली हैं। अब देखिए न, बिना माटी के तो हरी घास उग नहीं सकती है! बिना बारिश के भी हम रह नहीं सकते हैं! हमें हरी घास की भी चाह हो! पर वह बिना माटी और जल के उगे भी तो कैसे!

जो हो, महानगरों और शहरों में विशेष रूप से हमें हरी घास के 'दर्शन' चाहिए। फिर दोहरा दूं कि चाहे वह छोटे-से टुकड़े में ही क्यों न मिले! किसी फुटपाथ में किसी किनारी की तरह ही बसी हुई क्यों न हो! किसी चारदिवारी से लग कर बारिश में ही क्यों न उग आई हो, वह हो, वह हो, वह हो। बनी रहे।

घोटाले की मार

पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक में घोटाले की खबर आग की तरह फैली। न कोई भनक, न कोई अलर्ट और सीधे ग्राहकों के खाते जब्त। जब तक लोगों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही सब कुछ निपट चुका था और बैंक के बाहर भीड़ जमा थी। भारतीय रिजर्व बैंक की रुक-रुक कर आती डिजिटल सूचनाओं ने ग्राहकों के होश उड़ा दिए थे। नए युग की ओर बढ़ रहे भारत के करोड़ों गरीब परिवारों को बैंक खाते से जोड़ा गया। लेकिन सवाल तो यह है कि अब वे गरीब क्या करेंगे जिनकी पसीने की कमाई बैंकों में जमा है और अब वे छह मीहने में पच्चीस हजार रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे। कैसे खर्चा चलाएंगे? दरअसल, यही असली हिंदुस्तान है जहां नोटबंदी से लेकर पीएमसी घोटाले तक हर बार अपने पैसों के लिए गरीब को कतारों में धक्के खाने पड़े हैं। लोगों के बदन पर काले कपड़े हैं, हाथों में तख्तियां और होंठों पर मदद की गुहार!

● *एमके मिश्रा, मां आनंदमयीनागर, रातू*

मदद को हाथ बढ़ाएं

आपदा में, विपत्ति में, विषम परिस्थितियों में मदद के लिए हाथ उठना चाहिए। सरकार ने क्या किया, क्या नहीं या कहां चूक हुई, इस बहस के लिए काफी समय मिल जाएगा। मानवता का धर्म है कि हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें भी खाने का कोई अधिकार नहीं है। विकट परिस्थितियों में सरकार के भरोसे रहना या केवल कोसना भी ठीक नही है। भयावह स्थिति से निपटना केवल सरकार के बूते की बात नही है। अगर हमसे किसी को दो रोटी और एक ग्लास पानी भी जरूरतमंद को मिल जाता है तो यह मदद कम नहीं होगी। सोचिए, अगर दस लाख लोग यह प्रतिज्ञा कर लें तब इतने लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं। इसमें किसी दिखावे और तामझाम की जरूरत नहीं है। आप किसी से आत्मीयता के साथ कुशल क्षेम पूछ लेते हैं तो इतने मात्र से ही उसका हृदय भर आता है। हमें यह प्रण करना चाहिए कि थोड़ा-सा हिस्सा उन लोगों को भी दें जो वंचित हैं और त्योहारों की खुशी के मौके पर वे भी हमारी-आपकी तरह खुशी मना सकें।

● *प्रसिद्ध यादव, पटना*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

किसान की सुध

भारत का भाग्य विधाता और अन्नदाता कहे जाने वाला किसान आज कर्ज के तले इतना परेशान हो गया है कि उसे अपने प्राणों की आहुति देकर कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इसमे कोई संशय नहीं है कि किसानों के प्रति सरकार का रवैया कल्याणकारी है, परंतु सरकारी मशीनरी की लापरवाही और किसानों के लिए बनी योजनाओं को सही ढंग से लागू नहीं किया जाना इसका बड़ा कारण रहा है। आज भारत मे हर मिनट पांच किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में आवश्यकता है कि सरकार कर्ज माफी के इतर किसानों की खस्ता हालत सुधारे, ताकि किसान को कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े। वर्तमान में आवश्यकता अनाज के भाव मे वृद्धि की नहीं, अपितु भंडारण गृह बनाने की और उसको प्रोत्साहित करने की है ताकि निम्न दाम पर किसान अपनी फसल को उसमें रख कर उच्च दाम पर निर्यात कर सकें।

● *मनीष नागर, उज्जैन*

तंबाकू से बचाव

तंबाकू सेवन से जन्मे अनेक रोगों से बचने की सलाह हमेशा दी जाती है। इसकी बढ़ती लत के कारण भारत में मुंह और गले के कैंसर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तंबाकू में घातक रसायन निकोटिन पाया जाता है। स्वैच्छिक संगठन एवं सामाजिक संस्थाएं तंबाकू निषेध दिवस पर अपना राग अलापते-अलापते शायद थक गई हैं। आज भी स्थितियां वैसी ही हैं। परामर्श केंद्र भी जागरूकता लाने का प्रयत्न कर तो रहे हैं, लेकिन अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आ रहे। जागरूकता के साथ यह भी जरूरी है कि व्यसन मुक्ति केंद्र भी चिकित्सालय के समीप में ही होना चाहिए ताकि इलाज हेतु मरीज को एक ही स्थान पर सुविधा प्राप्त हो सके। बड़ी समस्या तो यह है कि तंबाकू सेवन से खतरों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों मे नहीं के बराबर है। कई बच्चे भी तंबाकू सेवन की लत के शिकार हैं। उन्हें समझाइश की जरूरत है। वर्तमान में कई जगह तो सड़कों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर थूके जाने पर जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि बच्चों, नौजवानों को असमय मौत का ग्रास बनने से बचाया जा सके।

● *संजय वर्मा, धार*

प्लास्टिक का खतरा

स्वच्छता का लक्ष्य और स्वच्छ भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं होता। हमारे देश में प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है। कूड़े के ढेर में सबसे ज्यादा पॉलिथिन थैलियां ही नजर आती हैं। प्लास्टिक के कचरे को जला कर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे जलाने से जहरीली गैसें निकलती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा बोतलों का भी होता है। प्लास्टिक का दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रयोग लोगों की सेहत पर तो भारी पड़ ही रहा है, साथ ही प्रकृति को दुषित करने और भूमि की उत्पादन क्षमता को भी कम कर रहा है। इससे भी ज्यादा गंभीर बाततो यह है कि आवारा पशु कचरा खा जाते हैं और इस तरह प्लास्टिक उनके पेट में पहुंच जाता है। पॉलिथिन की थैलियां नालों को जाम कर देती हैं और बारिश के पानी को भी जमीन में जाने से रोक देती हैं। धरती के लिए बड़ा संकट है। लोग कचरे के साथ प्लास्टिक तक जला डालते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इससे जो जहरीला धुआं निकलता है वह जानलेवा बीमारियों को भी जन्म देता है।

● *राजेश कुमार चौहान, जलंधर*

epaper.jansatta.com